एम. एम. पुंछी और उजागर सिंह, न्यायमूर्ति के समक्ष

गुरदयाल सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 9021 और सिविल विविध। 1988 का क्रमांक 13597.

6 अक्टूबर 1988.

ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चतुर्थ)- धारा 3(ए), 4 और 5- एक गांव में दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों के साथ दो सभा क्षेत्रों का निर्माण अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वीकार्य है- एक ही गांव में अलग-अलग ग्राम पंचायत बनाने की अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सभी पिछली अधिसूचनाओं को अधिक्रमण करते हुए" गाँव-कई अन्य को अधिक्रमण करते समय किसी विशेष पूर्व अधिसूचना का उल्लेख न करने का प्रभाव। कहा गया.

माना गया कि पंचायतें सभा क्षेत्रों से सह-संबंधित हैं और एक गांव में एक से अधिक सभा क्षेत्र और इस प्रकार एक से अधिक ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। इसलिए। ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 4 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) के तहत एक गांव में दो सभा क्षेत्रों का निर्माण अनुमत है। अनुभाग की भाषा सामान्य एवं सरल है। (पैरा 3).

माना कि वहाँ एक से अधिक सभा क्षेत्र होने की स्थिति में गाँव का नाम स्पष्ट रूप से एक ही रहेगाराजस्व संपत्ति से संबंधित जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अलग-अलग पहचान के प्रयोजनों के लिए वहां मौजूद सभी दो सभा क्षेत्रों के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, जो अनिवार्य रूप से गांव के समान नहीं हैं। (पैरा 4).

माना गया कि दोनों सभा क्षेत्रों की पहचान नाम से की गई है, भले ही गांव के नाम का उपयोग किया गया हो, लेकिन केवल सभा क्षेत्र के नाम के साथ इसे सहसंबंधित करने के लिए (पैरा 5).

माना गया कि अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें संबंधित सभा क्षेत्र शामिल हैं। चूंकि विशिष्ट नाम से दोनों सभा क्षेत्र करेरा खुर्द के नाम से जाने जाने वाले गांव में

हैं, इसलिए संबंधित सभा क्षेत्र के नाम के साथ सह-संबंधी कॉलम नंबर 2 में गांव के नाम का दो बार उल्लेख करना कोई गलत बात नहीं है। अधिनियम की धारा 4 और 5 का विवरण। (पैरा 6).

माना गया कि आक्षेपित अधिसूचना में, "सभी पिछली अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। फिर प्रतिस्थापित अधिसूचनाओं के नंबर दिए गए हैं। उसमें 1983 की अधिसूचना 'अनुलग्नक पी-5' को अधिक्रमण करने की चूक विवादित अधिसूचना, परिशिष्ट पी-4 के लिए घातक नहीं होगी, सबसे पहले, क्योंकि पिछली सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रमण कर दिया गया है और 1983 अधिसूचना का उल्लेख न करने मात्र से कोई मतलब नहीं होगा। अंतर और दूसरा अधिसूचना की भाषा से स्पष्ट है कि एक गांव में पहले जो एक सभा क्षेत्र था, उसके स्थान पर दो सभा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। (पैरा 7).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(i) अधिसूचना अनुलग्नक पी-4 को रद्द करते हुए जारी किया गया सर्टिओरारी का रिट, या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश;

(ii) अनुबंध पीए के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगाई जाए;

(iii) अनुबंध पीए के संचालन पर रोक लगाई जाए;

(iv) रिट नियमों के तहत अपेक्षित उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से मुक्त किया जा सकता है;

(v) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की भी छूट दी जाए

(vi) कोई अन्य राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले की परिस्थितियों के तहत पात्र पाए जाते हैं, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाती है।

(vii) इस रिट याचिका की लागत उन्होंने याचिकाकर्ता को दी।

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि इस रिट याचिका के लंबित होने तक, पंचायत के चुनाव आयोजित करने और आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/4 के संचालन पर न्याय के लिए रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील लखिंदर सिंह।

प्रतिवादी के लिए कोई नहीं।

आदेश

एम. एम. पुंछी, जे. (मौखिक)

(1) इस अदालत के समक्ष दो सिविल रिट याचिकाएँ संख्या 6153/88 और 7229/88, पहले गाँव करेरा खुर्द, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला के ग्रामीणों द्वारा क्रमशः 30 जून, 1988 तथा 1/2 अगस्त, 1988 को जारी की गई दो अधिसूचनाओं में गलती पाते हुए लाई गई थी। राज्य सरकार ने उन अधिसूचनाओं को एक के बाद एक सही करने का प्रयास किया। इस प्रकार, उन अधिसूचनाओं के तहत कुछ भी नहीं किया जा सका। अब चुनौती के तहत राज्य द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना 27 सितंबर, 1988 की है जो याचिका के अनुलग्नक पी.4 में है। सी.डब्ल्यू.पी. 28 सितंबर 1988 को 1988 का क्रमांक 7229 का निपटान करते समय हमें इसकी जानकारी दी गई थी।

(2) आक्षेपित अधिसूचना स्वयं बहुत कुछ कहती है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(3) पहली आपत्ति यह है कि एक गाँव में दो पंचायत नहीं हो सकते। गांव निस्संदेह एक है और वह है करेरा खुर्द। ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 4 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) में प्रावधान है कि सरकार अधिसूचना द्वारा 500 से कम आबादी वाले किसी भी गांव या निकटवर्ती गांवों के समूह को एक या अधिक सभा क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसके अलावा, पंचायतें सभा क्षेत्रों से सह-संबंधित होती हैं और एक गांव में एक से अधिक सभा क्षेत्र हो सकते हैं और इस प्रकार एक से अधिक ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। इसलिए, धारा 4 के तहत एक गांव में दो सभा क्षेत्रों के निर्माण की अनुमति है। धारा की भाषा सामान्य और सरल है।

(4) अगली आपत्ति यह है कि अधिनियम की धारा 3 (क्यू) के तहत, "गांव" का अर्थ किसी भी स्थानीय क्षेत्र से है, जो उस जिले के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व संपत्ति के रूप में दर्ज है जिसमें यह स्थित है। वहाँ एक से अधिक सभा क्षेत्र होने की स्थिति में गाँव का नाम स्पष्ट रूप से एक ही रहेगा क्योंकि यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राजस्व संपत्ति से संबंधित है। अलग-अलग पहचान के प्रयोजनों के लिए वहां मौजूद सभी दो सभा क्षेत्रों के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, जो अनिवार्य रूप से गांव के समान नहीं हैं।

(5) तीसरी आपत्ति यह है कि आक्षेपित अधिसूचना में यद्यपि दो सभा क्षेत्र बनाये गये हैं परन्तु गाँव का नाम दो बार प्रयोग किया गया है और यह अस्वीकार्य है। यह विवाद भी बिना किसी ताकत के है. दोनों सभा क्षेत्रों की पहचान नाम से की गई है, हालांकि गांव के नाम का उपयोग किया गया है, लेकिन केवल सभा क्षेत्र के नाम के साथ इसे सहसंबंधित करने के लिए। अतः कोई अवैधता नहीं है। यह अधिक से अधिक एक अनियमितता हो सकती है, जिसका प्रभाव शक्ति के प्रयोग पर नहीं पड़ेगा।

(6) अब अधिसूचना पर आते हैं कॉलम नंबर 2 में सभा क्षेत्र बनाने वाले गांव का नाम दिया गया है और कॉलम नंबर 5 में पंचायतों का नाम दिया गया है। चूँकि गाँव में दो पंचायतें बनाई गई हैं, इसलिए एक पंचायत या सभा क्षेत्र का नाम करेरा खुर्द-I और दूसरे का करेरा खुर्द-2 है। अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें संबंधित सभा क्षेत्र शामिल हैं। चूंकि दोनों सभा क्षेत्र विशिष्ट नाम से गांव में हैं, जिन्हें करेरा खुर्द के नाम से जाना जाता है, इसलिए संबंधित सभा क्षेत्र के नाम के साथ सह-संबंधी, कॉलम नंबर 2 में गांव के नाम का दो बार उल्लेख करना, कुछ ऐसा नहीं है जो कि गलत है। अधिनियम की धारा 4 और 5 का उल्लंघन। हम इसे तदनुसार रखते हैं।

(7) अंत में, यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित अधिसूचना में, हालांकि पहले की अधिसूचनाओं को हटा दिया गया है, वर्ष 1983 के अनुबंध पी.5 में अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत जारी अधिसूचना को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। आक्षेपित अधिसूचना में, "सभी पिछली अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में" एक अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। फिर प्रतिस्थापित अधिसूचनाओं के नंबर दिए गए हैं। उसमें 1983 की अधिसूचना 'अनुलग्नक पी. 5' को अधिक्रमण करने की चूक विवादित अधिसूचना परिशिष्ट पी. 4 के लिए घातक नहीं होगी, सबसे

पहले, क्योंकि पिछली सभी अधिसूचनाएं अधिक्रमण कर दी गई हैं और 1983 अधिसूचना का उल्लेख न करने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात अधिसूचना की भाषा से स्पष्ट है कि एक गांव में पहले जो एक सभा क्षेत्र था, उसके स्थान पर दो सभा क्षेत्र बनाये जा रहे हैं।

(8) निष्कर्ष के तौर पर, हमारा विचार है कि विवादित धारणा परिशिष्ट पी. 4 किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। नतीजतन, हम याचिका को तत्काल खारिज करते हैं।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी